समग्र एजेंडे के साथ भारतीय विदेश मंत्री की चीन यात्रा

डॉ. संजीव कुमार *

31 जनवरी से 3 फरवरी, 2015 के दौरान भारत की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की चीन यात्रा, जो दिल्ली में नई सरकार के किसी कैबिनेट मंत्री द्वारा की गई पहली चीन यात्रा है, द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। इस यात्रा में प्रदर्शित हुआ कि विदेश मंत्री के पास एक समग्र एजेंडा था, जिसमें न केवल कूटनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय वार्ताएं शामिल थीं, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसेकि पर्यटन और लोगों के आपसी संपर्क पर प्रकाश भी डाला गया और इसने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मई 2015 में होने वाली चीन यात्रा के लिए उपयुक्त माहौल का आधार तैयार किया।

विदेश मंत्री ने अपने समकक्ष श्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और बीजिंग में रूस-भारत-चीन के विदेश मंत्रियों की तेरहवीं त्रिपक्षीय बैठक में भी भाग लिया। श्रीमती सुषमा स्वराज ने राष्ट्रपति श्री शी चिनफिंग से भी मुलाकात की, जिन्होंने भारत-चीन संबंधों में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया और आशा व्यक्त की कि द्विपक्षीय संबंधों में 'नई प्रगति' होगी।

दूसरे 'भारत-चीन मीडिया मंच' की शुरुआत के मौके पर विदेश मंत्री के भाषण ने चीन के साथ भारत के भावी संपर्कों के लिए मंच तैयार कर दिया है। उन्होंने संज्ञान लिया कि भारत और चीन

'आर्थिक सहयोग को नए गुणात्मक स्तर' तक ले जाने के इच्छुक हैं। भारत में औद्योगिक पार्कों में प्रस्तावित चीनी निवेश और रेलवे में सहयोग सही दिशा में की गई पहलें हैं और ये नई सरकार द्वारा शुरू किए गए 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के अनुरूप हैं। निश्चित रूप से, भारत के बड़े व्यापार घाटे के मुद्दे को चीन के साथ गंभीरता से सुलझाने और आर्थिक संबंधों के साथ-साथ भारत और चीन के बीच व्यापार की वस्तुओं में विविधता लाने की आवश्यकता है।

विदेश मंत्री ने चीन के साथ एक व्यावहारिक और यथार्थवादी समझौते का प्रस्ताव रखा है और संबंधों का निर्माण करने के लिए छह सूत्री टेम्पलेट का सुझाव दिया है। ये हैं: कार्रवाई-उन्मुख दृष्टिकोण, व्यापक आधार वाले द्विपक्षीय संपर्क, साझा क्षेत्रीय और वैश्विक हितों पर सहमति, सहयोग के नए क्षेत्रों का विकास, कूटनीतिक संपर्क का विस्तार और एशियाई सदी में प्रवेश हेतु साझा आकांक्षाओं की पूर्ति करना। दूसरे शब्दों में, भारत-चीन संबंधों के भविष्य की दिशा के लिए एक तर्कसंगत रूपरेखा तैयार की गई है। यह छह सूत्री टेम्पलेट चीन के साथ सहयोगात्मक साझेदारी करने और एशियाई सदी को स्वरूप प्रदान करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब कूटनीति की असली परीक्षा गहन बातचीत के माध्यम से एक-दूसरे की मुख्य चिंताओं, आकांक्षाओं और संवेदनशीलता पर आम सहमति तक पहुँचने की होगी।

सीमा के प्रश्न पर श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि 'मेरी सरकार शीघ्र समाधान की तलाश के लिए प्रतिबद्ध है।' यह जानते हुए कि सीमा (विवाद) भारत और चीन के बीच एक प्रमुख मुद्दा है, दौरे पर गईं मंत्री का बयान सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया तेज करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। स्पष्ट रूप से, इस मुद्दे ने चीन के साथ-साथ भारत में भी महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया है। चीन के राज्य-संचालित अखबार *ग्लोबल टाइम्स* ने 10 फरवरी के अपने अंक में, सीमा (के मुद्दे) पर श्रीमती सुषमा स्वराज का बयान उद्धृत किया और यह स्वीकार भी किया कि दोनों देशों के मजबूत नेता 'लीक से हटकर समझौता' करने के लिए उत्सुक हैं। इस समाचार पत्र ने यह भी उल्लेख किया कि श्रीमती सुषमा स्वराज और उनके चीनी समकक्ष इस सहमति पर पहुंचे कि 'सीमा विवाद का समाधान भावी पीढ़ियों के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए।' यह इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण परिणाम है क्योंकि चीनी नेता सीमा मुद्दे को अलग रखते हुए आर्थिक मुद्दों से निपटने के मामलों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया करते थे।

विदेश मंत्री की चीन यात्रा ने कई मायनों में लोगों के आपसी संपर्क के महत्व को भी रेखांकित किया। 'भारत यात्रा वर्ष 2015' के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए, उन्होंने जोर दिया कि 'लोगों के आपसी संपर्क दो देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस संदर्भ में, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथूला दर्रे से होकर एक अतिरिक्त मार्ग का खोला जाना एक उल्लेखनीय पहल है। आखिरकार, भारत-चीन (संबंध) जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के लिए दोनों देशों के लोगों के व्यापक समर्थन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों ने लोगों के आपसी संपर्कों को मजबूत करने के लिए पर्यटन में सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति जताई।

रूस-भारत-चीन के विदेश मंत्रियों की त्रिपक्षीय बैठक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। रूस और चीन ने एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) में भारत की भागीदारी और शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में भारत की पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन का स्वागत किया। इसके अतिरिक्त, यह महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन (आयोजित करने) पर तीनों देशों के बीच आम सहमति बनी, जिसका प्रस्ताव पहली बार भारत ने 1996 में संयुक्त राष्ट्र में किया था। यह कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक संधि को स्वीकार करने के बाद (अब) इस क्षेत्र में तीनों देशों को प्रभावित करने वाली किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अफगानिस्तान के मुद्दे पर, त्रिपक्षीय मंच ने इस देश में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में संयुक्त राष्ट्र की 'प्रमुख समन्वयकारी भूमिका' का समर्थन किया। यकीनन, अफगानिस्तान के संबंध में भारत की स्थिति चीन की स्थिति की ही तरह है, और दोनों ही अफगानिस्तान में अपनी सेना की तैनाती के लिए उत्सुक नहीं हैं। तथापि, अफगानिस्तान में तालिबान पर दोनों देशों का रुख अलग–अलग है।

भारत-चीन संबंधों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व असाधारण हैं। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज की प्रथम चीन यात्रा ने चीन के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक तर्कसंगत ढांचा (तैयार करने का) प्रस्ताव किया है और प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावित चीन यात्रा को 'परिणामोन्मुख' बनाने हेतु मंच तैयार कर दिया है। भारत और चीन के बीच और अधिक समन्वय और सहयोग एशियाई सदी को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

***

डॉ. संजीव कुमार विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं।